हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 77? लखनऊ, बुधवार 29 अक्टूबर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

जोड़ा साहिब यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी

कहा, गुरु परंपरा ने भारत को दिया त्याग और बलिदान का संदेश

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु परंपरा ने भारत को केवल आस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र की रक्षा, सेवा और बलिदान का आदर्श भी दिया है। सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के पवित्र जोड़ा साहिब का लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ। यह यात्रा सिख समुदाय के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब से जुड़ी है, जो सिख आस्था का अत्यंत पवित्र प्रतीक मानी जाती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को अक्षुण्ण रखें और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी प्रेरणा पहुंचाएं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवाणी सुनी और यात्रा सदस्यों को पटुका पहनाकर सम्मानित किया। गुरुद्वारा कमेटी ने योगी को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा हमारी परंपरा में यह कहा गया है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं, वह स्थान रामराज्य की तरह पवित्र और पुण्यभूमि बन जाता है। यह यात्रा हमें उस गौरवशाली गुरु परंपरा से जोड़ती है, जिसने भारत की संस्कृति, साहस और बलिदान की भावना को नई दिशा दी। योगी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर शुरू हुई है। यह केवल श्रद्धा की यात्रा नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और राष्ट्र समर्पण की प्रेरणा देने वाली यात्रा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके चार साहिबजादों ने जिस प्रकार धर्म, देश और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वह भारत के इतिहास को नई प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग ढाई सौ वर्षों से गुरु महाराज के पावन चरण पादुकाएं, जो पहले अखंड भारत के हिस्से पाकिस्तान में थीं, अब पटना साहिब में स्थापित की जा रही हैं। दिल्ली से शुरू हुई यह यात्रा पूरे देश में गुरु परंपरा के प्रति सम्मान और गौरव का भाव जगाती जा रही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ का यहियागंज गुरुद्वारा इसलिए भी विशेष है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस स्थान से जुड़ी हैं। यह गुरुद्वारा हमारी साझा आस्था और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। योगी ने सिख समुदाय के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु परंपरा ने भारत को केवल आस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र की रक्षा, सेवा और बलिदान का आदर्श भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को अक्षुण्ण रखें और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी प्रेरणा पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख समाज की यह यात्रा केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे इस गुरु चरण यात्रा को राष्ट्रीय एकता और आध्यात्मिक जागरण के संदेश के रूप में आगे बढ़ाएं।

कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा-सरकार ने अग्निवीरों के साथ किया धोखा

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने सरकार पर अग्निवीरों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था लेकिन अब गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि रिटायर अग्निवीरों को देश की टॉप दस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों में रखा जाएगा। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल रोहित चौधरी ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में अधिसूचना को अग्निवीरों के साथ धोखा बताया और कहा कि यह योजना देश की सुरक्षा और युवाओं के लिए घातक है इसलिए इस योजना को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे जवानों के साथ सही नहीं कर रही है। ये साफ तौर पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले ही जय जवान अभियान चलाया था और अब जय जवान अभियान का दूसरा भाग चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश को कम प्रशिक्षित सैनिक दिए जा रहे हैं और मोदी सरकार सैनिकों की पेंशन काटकर अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरी भर रही है। कर्नल चौधरी ने कहा हम सभी वचनबद्ध हैं कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा और युवाओं के लिए घातक है, ये खत्म होनी चाहिए। मोदी सरकार अगर ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा काम करने वाले सैनिकों को प्रोत्साहन नहीं दे सकती थी तो उन्हें धोखा भी नहीं दिया जाना चाहिए था।

पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की वाले बयान पर भड़कीं मायावती

कहा- शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति-निन्दनीय

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी के पूर्व विधायक के विवादित बयान को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 'मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ, के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ–साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ना जाने क्या–क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर साम्प्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशान्ति, अराजकता एवं लोगों के जान–माल व मजहब पर खब्तरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति–निन्दनीय। उन्होंने कहा कि ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिये खुली चुनौती और खतरा हैं। इन्हें शह व संरक्षण देने के बजाय सरकार राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुये कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने

के लिये ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, यही व्यापक जन व देशहित में कार्य होगा। गौरतलब है कि डोमरियागंज से भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक विवादित बयान वायरल हो रहा है। वीडियो वह कहते दिखाई दे रहे हैं कि 'मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ विवादित बयान दें रहे हैं जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। हालांकि इस बयान पर अभी तक न ही भाजपा की तरफ से कोई बयान आया है न ही पूर्व विधायक ने ही कोई सफाई दी है।

मोदी–नीतीश सरकार ने युवाओं की आकांक्षाओं का गला घोंटा, बिहार को गढ़े में धकेला : राहुल

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में शिक्षा, रोजगार और मानव विकास की स्थिति का उल्लेख करते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि ''मोदी–नीतीश सरकार ने युवाओं की आकांक्षाओं का गला घोंट दिया है तथा प्रदेश को हर पैमाने पर गर्त में धकेल दिया है। उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई कर रहे बिहार के कुछ युवाओं के साथ संवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया मंच 'एक्स पर साझा किया। राहुल गांधी ने 'एक्स पर पोस्ट किया, ''कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से बहुत दिलचस्प बातचीत हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर मुद्दे पर। इन सबकी दुर्दशा के लिए सिर्फ एक गुनहगार है, भाजपा सरकार। उन्होंने दावा किया, ''बिहार के युवा बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों में किस तरह मोदी–नीतीश सरकार ने उनकी आकांक्षाओं का गला घोंटा है, प्रदेश को लावारिस छोड़ दिया है और हर पैमाने पर गर्त में धकेल दिया है। राहुल गांधी ने बिहार में शिक्षा की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा, ''कक्षा 9–10 में 'ड्रॉपआउट के मामले में बिहार का 29 राज्यों में 27वां स्थान है। कक्षा 11,12 में प्रवेश की दर के मामले में 28वां स्थान है तथा महिला साक्षरता के मामले में 28वां स्थान है। कांग्रेस नेता ने रोजगार की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवा क्षेत्र में रोजगार को लेकर बिहार का 29 राज्यों में 21वां स्थान है तथा उद्योग, उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के मामले में 23वां स्थान है।

केशव मौर्य का विपक्ष पर हमला, कहा, एसआईआर पर सवाल उठाने वाले लोकतंत्र के असली दुश्मन

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण (एसआईआर) की पहल लोकतंत्र को मजबूत करने वाली नेक कवायद है और जो राजनीतिक दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वे दरअसल लोकतंत्र के असली दुश्मन हैं। केशव मौर्य ने मंगलवार को एक्स पर लिखा वंशवादी दलों की पूरी राजनीति

चुनावी फर्जीवाड़े पर टिकी है। इसलिए जब भी कोई सुधारात्मक कदम उठाया जाता है, वे सबसे ज़्यादा हल्ला मचाते हैं। मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है और इससे केवल ईमानदार राजनीति को ही लाभ होगा। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा अब राज्य में जंगलराज की यादें मिट रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और विकास के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। सुशासन, पारदर्शिता और विकास ही एनडीए की पहचान है। जनता अब उन दलों को पहचान चुकी है जिनकी राजनीति केवल झूठ, भ्रम और परिवारवाद पर आधारित रही है। बिहार और पूरे देश में जनता अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थायी विकास और सशक्त लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रही है।

देशभर में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने संपन्न किया 36 घंटे का महाव्रत, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। छठ महापर्व का आज चौथा और अंतिम दिन है। देशभर में उपवास रखने वाली महिलाओं ने सुबह उदयमान सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित कर 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का समापन किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक छठ घाटों पर भक्ति और उत्साह की लहर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर छठ समापन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, भगवान सूर्यदेव को प्रातरुकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। चार दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और

श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन! छठी मइया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। लखनऊ के गोमती घाट, कुड़िया घाट और अन्य स्थानों पर रातभर महिलाएं जल में खड़ी रहीं। प्रातःकाल जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखी, ठेकुआ, फल और दूध से भरे सूप लिए महिलाओं ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में पर्व की रौनक साफ झलक रही थी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिसमें पुलिस बल और गोताखोर तैनात रहे। अयोध्या राम की नगरी में सरयू तट पर सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्रों में सूर्य को अर्घ्य दिया।

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया

संवाददाता

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग के संदर्भ को मंजूरी देने के फैसले का स्वागत किया है। आठवीं वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर केंद्र सरकार की एक करोड़ से भी अधिक कर्मचारी एवं पेंशनर्स को फायदा होगा तथा इसी के आधार पर राज्यों की कर्मचारी एवं पेंशनर्स को आठवीं वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आएगी लेकिन रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी। 1 जनवरी 2026 से उस दिन तक का एरिया कर्मचारियों को दिया जाएगा जिस तिथि से कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिलेगा। कैबिनेट के निर्णय से पुरानी पेंशन पर भी कर्मचारियों के बीच आश जगी है। आठवें वेतन आयोग की परिधि में कर्मचारियों के वेतन भत्तों, संरचना ,वर्किंग कंडीशन आदि पर विचार करने के साथ–साथ कर्मचारियों का अंशदान लिए बिना पेंशन पर आने वाले खर्च पर भी विचार करने का प्रकरण शामिल किया गया है। वेतन आयोग की परिधि में इसको शामिल किए जाने से कर्मचारियों में यह उम्मीद जगी है कि सरकार पेंशन योजना को और अधिक लाभकारी बनाते हुए कर्मचारियों से लिया जाने वाला अंशदान समाप्त करने पर विचार कर सकती है। यदि कर्मचारियों से अंशदान लिए बिना सरकार पेंशन सुविधा देने पर विचार करती है तो यह पुरानी पेंशन की वापसी के बराबर ही होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने जनवरी में ही केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग की घोषणा पर बधाई दिया था तथा केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई सूचना के आधार पर न्यूनतम वेतन संरचना एवं पुरानी पेंशन पर एक विस्तृत पत्र प्रदेश के वित्त विभाग के माध्यम से प्रेषित किया था। वर्तमान में अब जब केंद्रीय आठवें वेतन आयोग का विधिवत गठन हो जाने की कैबिनेट मंजूरी सरकार ने दे दिया है तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए अपना प्रतिवेदन केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी। केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के संदर्भ के अनुमोदन के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की तरफ से संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष, निरंजन कुमार श्रीवास्तव ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, प्रीति पांडे ,सर्वेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र वीर यादव, शिवकांत द्विवेदी, कुसुम लता यादव सहित संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।

यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले, तीन कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारी इधर-उधर

डीएम कौशाम्बी मधुसूदन हुल्गी बने विशेष सचिव मुख्यमंत्री

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 46 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तीन मंडलायुक्त और दस जिलों के डीएम बदले हैं। मिर्जापुर विंध्याचल सहारनपुर और मेरठ के कमिश्नर बदल दिए गए हैं। हाथरस, सीतापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, कौशांबी, बलरामपुर, ललितपुर, श्रावस्ती, रामपुर के जिलाधिकारियों को बदल दिया गया है। वाराणसी तैनात चार आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों को बदला गया है। मुख्य विकास अधिकारी, विकास प्राधिकरण

के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त और एडीएम फाइनेंस को बदला गया है। विंध्याचल के मंडलायुक्त बाल कृष्ण त्रिपाठी को सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन में सचिव बनाया गया है। महानिदेशक मत्स्य राजेश प्रकाश अब विन्ध्याचल के मंडलायुक्त होंगे।राज्य मानवाधिकार आयोग की सचिव के. ६ानलक्ष्मी को महानिदेशक मत्स्य बनाया गया है। महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम संजय कुमार को वर्तमान पद के साथ सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रबंध निदेशक राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा प्रबंधनिदेशक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड डा. रूपेश कुमार को अब मंडलायुक्त सहारनपुर बनाया गया है। मंडलायुक्त सहारनपुर अटल कुमार राय को सचिव गृह विभाग बनाया गया है। सचिव, राजस्व विभाग राहत आयुक्त तथा चकबंदी आयुक्त भानु चन्द्र गोस्वामी अब मेरठ के कमिश्नर होंगे।मंडलायुक्त मेरठ डा. ह्रषिकेश भास्कर यशोद सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन, राहत आयुक्त एवं चकबंदी आयुक्त बने है ।मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण मयूर माहेश्वरी को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड बनाया गया है ।सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग विजय किरन आनंद को वर्तमान पद के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रभारी एनआरआई सेल एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लीडा के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ।जिलाधिकारी हाथरस राहुल पाण्डेय को विशेष सचिव राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन बनाया गया है ।उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अतुल वत्स को जिलाधिकारी हाथरस बनाया गया है ।जिलाधिकारी ललितपुर अमनदीप डुली को अपर आयुक्त, मनरेगा उत्तर प्रदेश बनाया गया है। मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी हिमांशु नागपाल को नगर आयुक्त वाराणसी बनाया गया है। मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक अलीगढ प्रखर कुमार सिंह को सीडीओ वाराणसी बनाया गया है ।उपनिदेशक मंडी परिषद लखनऊ योगेन्द्र कुमार को मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक अलीगढ बनाया गया है। जिलाधिकारी सीतापुर अभिषेक आनंद को विशेष सचिव आबकारी विभाग बनाया गया है ।जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर राजागणपति आर को जिलाधिकारी सीतापुर बनाया गया है। विशेष सचिव राज्य कर विभाग कृत्तिका ज्योत्सना को जिलाधिकारी बस्ती बनाया गया है ।जिलाधिकारी बस्ती रवीश गुप्ता को प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ बनाया गया है। प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ ईशा दुहन को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड बनाया गया है। प्रबंध निदेशक सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड कुमार विनीत को विशेष सचिव युवा कल्याण एवं खेल विभाग बनाया गया है ।जिलाधिकारी चित्रकूट शिवशरणप्पा जीएन को जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर बनाया गया है।

महागठबंधन का घोषणा पत्र 20 साल में जनता के साथ हुए धोखे को सुधारने का रास्ता : पवन खेड़ा

एजेंसी

पटना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने मंगलवार को दावा किया है कि 20 साल में एनडीए ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। इस बिहार चुनाव में महागठबंधन का घोषणा पत्र जनता के साथ हुए धोखे को सुधारने का रास्ता होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनावी अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। इसके बाद सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कई कार्यक्रम तय हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जननायक कहे जाने पर उपजे विवाद पर खेड़ा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर से कोई मुकाबला नहीं है, वह देश के महान नेता हैं। हम उनसे कोई तुलना नहीं कर रहे। यह विवाद पैदा करने की कोशिश भाजपा करती है। भाजपा के पास दूसरा मुद्दा नहीं है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हर जगह विवाद करना भाजपा के वैचारिक दिवालियापन को दिखाता है। उनके पास कुछ ठोस नहीं है, सिर्फ संकीर्णता है। केंद्रीय मंत्री किरेण रिजिजू के तेजस्वी यादव पर दिए बयान पर खेड़ा ने कहा कि जो ये कह रहा है, वो खुद अपरिपक्व हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले एसआईआर को लेकर खेड़ा ने कहा कि बिहार में जो एसआईआर हुआ, उसके लिए बार–बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग की नियत पर शक था। आयोग ने डोर–टू–डोर कैंपेन नहीं किया।

संपादकीय

बेरोजगारी की बेड़ियां

अमानवीयता की हद पार करती अमेरिका इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी के संवेदनहीन तौर–तरीकों का त्रास झेलते 54 हरियाणवी युवा शनिवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे। सुनहरे सपनों की आस लिए अमेरिका गए इन युवाओं ने जिन त्रासदियों का सामना किया, वो उन युवाओं के लिये सबक भी है, जो अपनी योग्यता व क्षमता का मूल्यांकन किए बिना बस विदेश जाने की धुन में लगे रहते हैं। निस्संदेह, इन युवाओं ने बेहतर भविष्य के लिये रिस्क लेने का जज्बा तो दिखाया, लेकिन एजेंटों के छलावे के चलते डंकी रूट पर फिसल गए। इन युवाओं को इस बात का भान नहीं रहा कि घोर दक्षिणपंथी रुझान वाले ट्रंप के शासन में प्रवासियों के साथ कैसी क्रूरता व भेदभाव किया जा रहा है। जिसके चलते उनके साथ अमेरिका में अपराधियों जैसा सुलूक किया है। उन्हें जेल और अपराधियों के लिये बने कैंपों में रखा गया। युवाओं ने आरोप लगाया कि जेलों में गर्मी में हीटर और सर्दी में एसी चलाकर रखा जाता था। शाकाहारियों को मांस दिया जाता था और न खाने पर सिर्फ सूखी रोटी। खेत बेचकर–कर्ज लेकर उज्ज्वल भविष्य के लिये अमेरिका गए युवा अपराधियों की तरह स्वदेश लौटे। समाचार माध्यमों में प्रकाशित चित्रों में इन हताश युवाओं को अपराधबोध से ग्रसित देखा गया। विडंबना देखिए कि कई युवा अपना खेत बेचकर और चालीस–पचास लाख एजेंट को देकर विदेश गए, लेकिन डंकी रूट में धकेल दिए गए। उस खतरनाक रास्ते पर जहां हर पल मौत का खतरा बना रहता है। परिवार वालों को इस बात का सुकून जरूर होगा कि कम से कम उनके बच्चे सकुशल तो घर लौट आए है। वो बात अलग है कि इन युवाओं को अपने असफल प्रयास का मलाल जीवनपर्यंत सालता रहेगा। कुछ युवा इससे अवसादग्रस्त हो सकते हैं। कुछ हताश युवा भटकाव की राह में गुजर सकते हैं। निश्चय ही यह घटनाक्रम इन युवाओं के लिये एक त्रासदी से कम नहीं रहेगा। सुखमय जीवन की आस ने नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया। वे बेड़ियों में देश लौटे। बहरहाल, इन युवाओं की अपमानजनक वापसी कई ज्वलंत सवालों को भी जन्म देती है। यह हमारी नीति–नियंताओं की विफलता ही है कि हम युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दे पा रहे हैं। हम कहते नहीं थकते कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सवाल यह है कि इस युवा शक्ति को दिशा देने के लिये हमने क्या किया? तमाम प्रलोभन व लोकलुभावने वादे करने वाले राजनीतिक दलों की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना क्यों नहीं होती? सिर्फ चुनाव आने पर करोड़ों रोजगार देने के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बावजूद वे पूरे नहीं होते। दोष हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी है जो डिग्री तो देती है, लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं देती। दोष हमारी युवा पीढ़ी की उस मानसिकता का भी है जो सिर्फ नौकरी और उसमें भी सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देती है। निजी क्षेत्र भी सिर्फ मुनाफे को प्राथमिकता देता है और तकनीक के जरिये रोजगार के अवसरों में कटौती को प्राथमिकता देता है। ऐसे देश में, जहां आबादी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमें श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिसमें अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। कायदे से देश में बेरोजगारी का ग्राफ देखते आने वाले दशकों के लिये रोजगार का रोडमैप बनना चाहिए। लेकिन सत्ता भी सस्ती लोकप्रियता वाले कामों के जरिये अपना वोट बैंक सुधारने में लगी रहती है। यहां सवाल युवाओं व अभिभावकों की सोच का भी है, जो खेत बेचकर बेटे को विदेश भेजने की फिराक में रहते हैं। जितना पैसा उन्होंने विदेश भेजने वाले एजेंटों को दिया, उसमें क्या वे स्वरोजगार नहीं कर सकते थे? माना कि आज खेती–किसानी युवाओं को नहीं लुभाती, लेकिन वे इस खेत पर गैर परंपरागत खेती व फल–फूल आदि नकदी फसलों के विकल्प तो तलाश सकते हैं। सवाल हमारी प्रवर्तन एजेंसियों पर है कि क्यों युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों पर कार्रवाई नहीं करती, जो लाखों रुपये लूटकर इन्हें नर्क में धकेल देते हैं। वापस आए इन युवाओं के जरिये उन तक पहुंचा जा सकता है।

राशिफल

मेष :– काफी दिनों से अवरोधित कोई हल होने के आसार बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में किया गया प्रयत्न सार्थक होगा। रोजगार में लाभकारी अवसर मिलेंगे।

बृषभ :– भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी। अतः व्यवहार कुशल बने। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न बरतें। घर में खुशहाल वातावरण रहेगा।

मिथुन :– मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरें में जाया न करें। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। सकारात्मक सोच को अपनाते हुए जीवन को सही दिशा की ओर केंद्रित करें और परिवार के अनुकूल चलें।

कर्क :– नये व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। संवेदनशील शरीर ग्रहां की प्रतिकूलता से बीमार पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। पुरानी घटनाओं से मन को कष्ट संभव।

सिंह :– नयी घरेलू जिम्मेदारियों के पैदा होने से व्यय संभव। अच्छे कायरें से परिजनों के दिल में जगह बनायें। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। महत्वपूर्ण कायरें में लापरवाही कतई न करें।

कन्या :– जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। नये कायरें के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। नये क्षेत्रों में प्रयास से लाभ संभव। व्यावसायिक यात्रा द्वारा लाभ होगा। संबंधियों के सहयोग से कठिनाइयां दूर होंगी।

तुला :– भविष्य को लेकर मन नकारात्मक आशंकाओं से प्रभावी रहेगा। प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन भाव प्रतिभाओं के लाभ से वंचित करेगा। सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

वृश्चिक :– रोजगार संबंधी कुछ नयी योजनाओं पर मन केंद्रित होगा। किसी कार्य में सफलता से उत्साह में वृद्धि होगी। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयत्न करें। भौतिक सुख में वृद्धि होगी।

धनु :– अपनी बातूनी कला का लाभ उठाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। परिश्रम से आर्थिक लाभ का योग है। समस्याओं के समाधान से उत्साह में वृद्धि होगी।

मकर :– बीती बातों को सोचने के बजाय वर्तमान में जीने की चेष्टा करें। जरूरत से ज्यादा बोलना व्यक्तित्व पर कुप्रभावी होगा। अतरू इसे सुधारें। नीरस स्वभाववश रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में असमर्थ होंगे।

कुंभ :– सब कुछ सामान्य होते हुए भी मन अरुचि का शिकार होगा। थोड़ा संयमी व धैर्यवान बने। भाग्य से प्राप्त सभी स्थितियों के मध्य समझौतावादी रवैया अपनायें। कुछ नई व्यस्तताएं सामने आएंगी। आलस्य कतई न करें।

मीनः– कुछ व्यासायिक कारणों से घर से दूर रहना पड़ सकता है। परिजनों की सुख–सुविधा के प्रति मन चिंतित होगा। मस्त–मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह के प्रति मन चिंतित होगा। मस्त–मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह होगा।

नौकरशाही, सत्ता और संवेदनहीनता

जब शासन सेवा से अधिक अहंकार बन जाए – फ़ाइलों के बीच मरती संवेदनाएँ, सत्ता का चेहरा संवेदना का शून्य बनकर, लोकतंत्र को मशीन बना देता है जहाँ नियम ज़्यादा हैं और रिश्ते कम

–डॉ. सत्यवान सौरभ

हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि समाज अन्याय से भर गया है, बल्कि यह है कि संवेदनाएँ खोती जा रही हैं। जिस देश में शासन–व्यवस्था "सेवा" का प्रतीक होनी चाहिए थी, वहाँ अब "नौकरशाही" शब्द ही "अहंकार" और "दूरदर्शिता की कमी" का पर्याय बन चुका है। सत्ता और नौकरशाही का यह गठजोड़ जब संवेदनहीनता के साथ मिलता है, तो व्यवस्था का चेहरा निर्दयी हो जाता है। आज आम नागरिक के लिए सरकार एक जीवित संस्था नहीं, बल्कि एक मशीन बन चुकी हैकृ जिसमें भावनाओं की जगह नियमों का बोझ है। एक छोटी–सी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति फ़ाइलों के जंगल में भटकता है। फोन उठाने से लेकर जवाब देने तक हर कदम पर एक दीवार खड़ी है कृ उस दीवार का नाम है नौकरशाही की असंवेदनशीलता। फ़ाइलों में दबे चेहरे और खोती मानवीयता नौकरशाही का मूल उद्देश्य नागरिकों की सुविधा, प्रशासन की पारदर्शिता और नीतियों की समानता था। लेकिन धीरे–धीरे यह वर्ग अपने ही बनाए दायरे में कैद हो गया। सत्ता के निकट रहकर उसने "सेवा" को "सत्ता–साझेदारी" में बदल दिया। आज अधिकारी जनता के प्रतिनिधि नहीं, सत्ता के प्रतिनिधि बन चुके हैं। फ़ाइलों पर फैसले अब संवेदना से नहीं, "किसे खुश करना है और किससे बचना है" जैसी मानसिकता से लिए जाते हैं। इस मानसिकता ने शासन को जीवंतता से दूर कर दिया है। नौकरशाही अब अपने भीतर एक ऐसा 'प्रशासनिक अहंकार' पाल चुकी है जो हर आलोचना को शत्रुता समझता है। फ़ाइलें महीनों दबाई जाती हैं, नियुक्तियाँ वर्षों तक लंबित रहती हैं, और जब जवाब माँगा जाए तो कहा जाता है कृ "प्रक्रिया में है।" यह "प्रक्रिया" अब बहाने का दूसरा नाम बन चुकी है। जनता के सवालों का जवाब काग़ज़ों में मिलता है, लेकिन न्याय का उत्तर शून्य में खो जाता है। सत्ता की चकाचौंध और जिम्मेदारी का अंधकार सत्ता अपने स्वभाव में आकर्षक होती है। यह व्यक्ति को शक्ति देती है, पर उसी शक्ति के साथ चरित्र की परीक्षा भी लेती है। दुर्भाग्य से, हमारे समय की राजनीति ने इस शक्ति को "जिम्मेदारी" नहीं बल्कि "विशेषाधिकार" समझ लिया है। सत्ताधारी तब तक सक्रिय रहते हैं, जब तक प्रशंसा मिलती रहती है। लेकिन आलोचना या असहमति के क्षणों में उनकी सहनशीलता समाप्त हो जाती है। यही संवेदनहीन सत्ता का भयावह रूप हैकृजहाँ जनता की पीड़ा आँकड़ों में बदल दी जाती है और आँकड़ों की भाषा में संवेदना मर जाती है। हर बार जब कोई त्रासदी होती है – दुर्घटना, दंगा, या भ्रष्टाचार कृ तब सत्ताधारी वर्ग कुछ ट्वीट और बयान जारी कर अपने "कर्तव्य" की इतिश्री मान लेता है। वहीं, ज़मीनी स्तर पर प्रशासन केवल रिपोर्ट तैयार करता है, जिनमें संवेदना नहीं, केवल डेटा होता है। यह स्थिति लोकतंत्र के उस आत्मा को चोट पहुँचाती है जो "जन" से शुरू होकर "जन" पर ही समाप्त होती है। संवेदनहीनता की जड़ें समाज में भी संवेदनहीनता केवल प्रशासन की नहीं, समाज की भी बीमारी बन चुकी है। आज दुर्घटनाओं के वीडियो बनाए जाते हैं, पर किसी को उठाने की हिम्मत कम ही होती है। गरीब की पीड़ा पर ताली बजाना आसान है, पर मदद करना कठिन। यह वही मानसिकता है जिसने सत्ता और जनता के बीच गहरी खाई बना दी है। जहाँ ऊपर बैठे लोग 'नीतियों' की बात करते हैं, वहीं नीचे खड़े लोग 'रोटी' की। बीच में है नौकरशाही कृ जो पुल नहीं, दीवार बन चुकी है। यही वह त्रासदी है जो लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर रही है। जनता और शासन के बीच का यह संवादहीनता का अंतराल एक दिन लोकतंत्र की जड़ें हिला सकता है। जनसेवक से "सरकार" बनने की यात्रा एक समय था जब सरकारी अधिकारी "जनसेवक" कहलाते थे। यह शब्द अब मज़ाक लगता है। आज का प्रशासन इतना प्रक्रियात्मक हो गया है कि वह मनुष्यता को भूल गया है। फ़ाइलों और कानूनों की दुनिया में "संवेदना" को "अपवाद" मान लिया गया है। यह विचलित करने वाली सच्चाई है कि जो तंत्र जनता की सेवा के लिए बना, वही तंत्र अब नागरिक को संदेह की दृष्टि से देखता है। अधिकारी जनता को सुविधा देने से अधिक उसके इंटेंशन पर शक करने लगे हैं। यह शक लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है। नौकरशाही और सत्ता के बीच यह मानसिक दूरी अब सामाजिक असमानता को और गहरा रही है। गाँवों में सड़क तब पहुँचती है जब वोट की ज़रूरत पड़ती है। स्कूलों में शिक्षक तब लगते हैं जब मीडिया हंगामा करती है। अस्पतालों में दवा तब आती है जब मंत्री का दौरा तय होता है। यह संवेदनहीन तंत्र आम नागरिक की ज़िंदगी को उस "प्रतीक्षा की यातना" में बदल देता है जो कभी समाप्त नहीं होती। शासन की विफलता नहीं, संवेदना का पतन संवेदनहीनता की यह संस्कृति सत्ता की स्थायी साथी बन चुकी है। सत्ता को केवल "नियंत्रण" चाहिए, उसे "सुनना" नहीं आता। इसी वजह से शासन का अर्थ "शासन करना" रह गया है, "समझना" नहीं। लोकतंत्र तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें संवाद और सहानुभूति बनी रहती है। लेकिन जब सत्ता और नौकरशाही दोनों जनता से दूर हो जाएँ, तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिकता बन जाता है कृ एक उत्सव जो हर पाँच साल में मनाया जाता है। हम यह भूल चुके हैं कि शासन का सार मनुष्यता में निहित है। कानून तभी तक उपयोगी हैं जब वे मानवीयता की रक्षा करें, और प्रशासन तभी तक वैध है जब वह नागरिक के दुख को अपनी जिम्मेदारी माने। आज हमारे देश में हर विभाग में योजनाएँ हैं, लेकिन क्रियान्वयन में संवेदना नहीं है। यही कारण है कि योजनाएँ "रिपोर्ट कार्ड" बनकर रह गई हैं, न कि राहत का साधन। नव–लोकतंत्र की चुनौती और सुधार का मार्ग जरूरत इस बात की है कि सत्ता को फिर से सेवा का पर्याय बनाया जाए। अधिकारी और नेता दोनों यह समझें कि उनके पद विशेषाधिकार नहीं, जिम्मेदारी हैं। हर निर्णय के पीछे केवल नियम नहीं, जीवन छिपे होते हैं। फ़ाइलें तब तक अर्थहीन हैं जब तक उनमें इंसान की कहानी नहीं झलकती। अब समय आ गया है कि शासन में इमोशनल इंटेलिजेंस को नीतिगत अनिवार्यता बनाया जाए। नौकरशाही को प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रोटोकॉल नहीं, संवेदना भी सिखाई जाए। पद का अहंकार अगर सेवा की भावना से नहीं मिला, तो हर नीति अधूरी रह जाएगी। आज आवश्यकता "अकुशल प्रशासनिक मशीनरी" की नहीं, "मानवीय प्रशासन" की है कृ जहाँ प्रत्येक निर्णय के केंद्र में नागरिक का दुःख, उसकी गरिमा और उसका जीवन हो। लोकतंत्र को पुनः जीवित करने की पुकार हमारे समय का असली सुधार यही होगा कि नौकरशाही और सत्ता में संवेदना वापस लाई जाए। कानून की कठोरता के साथ मानवीयता की कोमलता भी जरूरी है। क्योंकि इतिहास गवाह है कृ जहाँ शासन ने मनुष्य की पीड़ा को अनसुना किया, वहाँ क्रांति ने जवाब दिया। लोकतंत्र का सौंदर्य उसकी करुणा में है, उसकी कठोरता में नहीं। आज अगर हम नौकरशाही और सत्ता के बीच फिर से मनुष्यता को जीवित नहीं कर पाए, तो अगली पीढ़ियाँ हमें "संवेदनहीन युग" कहकर याद करेंगी।

और शायद तब यह प्रश्न गूँजेगा –
"क्या हमने शासन को इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया?"
इसलिए समय की पुकार है –
प्रशासन को प्रक्रिया से पहले मनुष्य को देखना सीखना होगा,
और सत्ता को शासन से पहले सुनना।

खानपान में खामी पर रेलयात्री के अधिकार

वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को दिये जाने वाले खानपान की गुणवत्ता में कमी समेत कई तरह की लापरवाहियां सामने आयी हैं। हालांकि यात्रियों की शिकायतों पर आईआरसीटीसी ने इन मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि किसी भी तरह की सेवा में कमी होने पर पीड़ित यात्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। देश मे वंदे भारत ट्रेन सबसे आरामदायक व तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। तभी तो इसका किराया भी अन्य ट्रेनों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यात्री इस ट्रेन में यात्रा करते समय सबकुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में यात्रा व भोजन में कोई असुविधा हो जाए तो उनका नाराज होना स्वाभाविक है। हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के दौरान एक यात्री ने एक्सपायरी डेट का फूड सर्व किए जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। इस मामले में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने यात्री से माफी मांगते हुए सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। यात्री ने एक्सपायरी डेट के फूड पैकेट और केचअप देने को लेकर सवाल उठाया था। शिकायत में दिए गए खाने को 1–2 दिन एक्सपायरी डेट का होना बताया है, जबकि 'ट्रेन के सुप्रिंटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि खाने की चीजों का ध्यान रखा जाए, लेकिन लापरवाही के चलते ही दो साल पुराना केचअप दिया गया। बीती 27 अगस्त को प्रशांत यादव नामक यात्री ने की गई शिकायत में कहा कि गोरखपुर से पाटलिपुत्र पटना तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में 2–3 साल पुराना एक्सपायरी डेट का खाना मिल रहा है। जिस पर आईआरसीटीसी ने खुद जवाब दिया है और यात्री को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। एक्सपायरी डेट के फूड पैकेट से जुड़े उक्त मसले पर आईआरसीटीसी ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। वहीं निगम ने कहा कि उन्होंने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। ऑन–बोर्ड कैटरिंग सुपरवाइजर को निर्देश दिया गया है कि वे सेवा कर्मचारियों को इस बारे में सलाह दें ताकि सेवा से पहले सभी खाद्य वस्तुओं की समाप्ति तिथि की जांच सुनिश्चित की जा सके। इसी से मिलते–जुलते दूसरे मामले में एक अन्य यात्री की शिकायत थी कि उनको भी खराब खाना खिला दिया गया,जिससे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में भी भोजन और पानी से जुड़ी शिकायतें लगातार आ रही हैं। इनमें भोजन समय पर नहीं मिलने की भी शिकायतें शामिल हैं। इसे लेकर वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत में दो लाख से अधिक का जुर्माना खानपान उपलब्ध कराने वाली फर्म पर लगाया जा चुका है। वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत में पिछले दो माह के अंदर खानपान की गुणवत्ता से जुड़ी 20 से अधिक शिकायतें मिली हैं। पटना–लखनऊ वंदे भारत में यात्री डॉ. हेमंत यादव को बोतलबंद गर्म पानी और बासी नाश्ता परोस दिया गया। उन्होंने रेल मंत्री को एक्स पर ट्वीट कर शिकायत की तो कैटरिंग मैनेजर ने दूसरा पैकेट नाश्ता और पानी उपलब्ध कराया। नई दिल्ली–वाराणसी वंदे भारत से सफर के दौरान यात्री वैभव सिंह को पापड़ जैसी सूखी रोटी परोस दी गई। यात्री ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट समेत एक्स पर शिकायत कर दी। हरकत में आए कैटरिंग मैनेजर ने तुरंत दूसरा भोजन उपलब्ध कराया। वैभव की शिकायत को बाद में डिलीट कर दिया गया। वहीं कानपुर सेंट्रल पर वंदे भारत में किसी यात्री को बैठाने जा रहे एक व्यक्ति के भी ट्रेन में चढ़ जाने पर वंदे भारत का दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन चल दी। आखिरकार वंदे भारत दिल्ली पहुंच गई। इस दौरान यात्री के साथी को बिना टिकट यात्रा करने पर 2870 रुपये का जुर्माना देना पड़ा। वंदे भारत ट्रेन में लापरवाही की ऐसी कई घटनाओं के बाद से रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करना शुरू किया है। साथ ही वंदे भारत ट्रेन में खानपान सेवाओं से संबंधित यात्रियों की शिकायतों की बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है। इसमें सीआरआईएस और आईआरसीटीसी को एक साथ काम करने और यात्रियों को एसएमएस भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उन्हें खाद्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाये। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी भी तरह की सेवा में कमी होने पर पीड़ित यात्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराकर न्याय प्राप्त कर सकता है।

–लेखक उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

आरएसएस नाजियों को फॉलो कर रहा है, पं. जवाहरलाल नेहरू

–कुमार रबींद्रनाथ तालुकदार

लोग अक्सर पूछते हैं कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों में से, पं. जवाहरलाल नेहरू ही दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा का मुख्य निशाना क्यों हैं? इसे समझने के लिए, 7 दिसंबर, 1947 को नेहरूजी द्वारा मुख्यमंत्रियों को लिखे गए इस पत्र को देखें। नेहरूजी ने 1947 में जो कहा था, वह 2025 में भी सच लगता है। नेहरू जी कहते हैं, हमारे पास इस बात के काफी सबूत हैं कि आरएसएस अपने स्वभाव से, प्राइवेट सेनाओं जैसा एक संगठन है, जो साफ तौर पर पॉलिसी और संगठन के मामले में नाजियों को फॉलो कर रहा है। हमारा मकसद नागरिक स्वतंत्रता में दखल देना नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देना और उनका इस्तेमाल करने का इरादा रखना, ऐसी चीज नहीं है जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सच तो यह है कि आरएसएस मौजूदा केंद्र और प्रांतीय सरकारों के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करना काफी नहीं माना जा सकता। जायज प्रोपेगेंडा की इजाजत जरूर होनी चाहिए। लेकिन उनके काम लगातार उस लाइन को पार कर रहे हैं। अब प्रांतीय सरकारों के लिए उन पर नजर रखना और जरूरी कदम उठाना जरूरी है। कुछ प्रांतीय सरकारों ने कुछ ऐसे पब्लिकेशन के खिलाफ कार्रवाई की है जो समुदायों के बीच नफरत फैलाते हैं। पाकिस्तान के अखबारों के अलावा, अगर इस मामले में किसी अखबार को सबसे ज्यादा दोषी ठहराया जा सकता है, तो वे आरएसएस के अखबार होंगे। यह हैरानी की बात है कि वे पूरी ताकत से अपना सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा कैसे जारी रखे हुए हैं। मुझे जर्मनी में शुरू हुए नाजी आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी है। इसने अपने बाहरी दिखावे और सख्त अनुशासन से लोगों को आकर्षित किया। इसमें कई निम्न–मध्यम वर्ग के युवा लड़के और लड़कियां शामिल थे। ये लोग आम तौर पर बहुत काबिल नहीं थे, और न ही जीवन में उनके पास ज्यादा मौके थे। इसलिए, वे नाजी पार्टी की ओर मुड़ गए क्योंकि उसकी पॉलिसी और प्रोग्राम बहुत आसान थे। वे नेगेटिव थे और उनमें दिमाग का एक्टिव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। नाजी पार्टी ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत में भी ये प्रवृत्तियां इसी तरह बढ़ती रहीं, तो वे भारत को भी बहुत नुकसान पहुंचाएंगी।

जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की कटुता कम होगी तो भारत व अन्य देश भी लाभान्वित होंगे!

–कमलेश पांडे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आसियान बैठक के बहाने हुई मुलाकात में मुख्यतः व्यापारिक तनाव को कम करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर गम्भीरता पूर्वक चर्चा हुई। बताया जाता है कि दोनों देशों ने टैरिफ, निर्यात नियंत्रण, कृषि उत्पादों के व्यापार, और फेंटेनाइल तस्करी जैसे अहम मसलों पर बातचीत की। खास बात यह रही कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने चीन पर फेंटेनाइल की तस्करी का आरोप लगाया, जिसे ट्रंप ने अपनी बातचीत का मुख्य मुद्दा बनाया। इसके अलावा, रूस से तेल खरीद, अमेरिकी किसानों से आयात, व्यापार असंतुलन जैसे विषय भी बैठक में उठाए गए। यही वजह है कि दोनों देशों ने व्यापार युद्ध को खत्म करने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए बुनियादी सहमति पर पहुंचने की कोशिश की है। गौरतलब है कि दोनों देशों ने ही मुलाकात की पुष्टि की है, और यह माना जा रहा है कि संबंधों में सुधार की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक, जहां ट्रंप ने आने वाली पहली बातचीत में फेंटेनाइल मुद्दा उठाने की बात कही है, वहीं शी जिनपिंग ने भी वार्ता को रचनात्मक बताया। अगली मुलाकात आगामी 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया के बुसान में होगी, जहां एपीईसी सम्मेलन भी आयोजित हो रहा है। इस बैठक में ताइवान और हांगकांग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रंप ने लोकतंत्र समर्थक नेता जिमी लाई की रिहाई का मुद्दा उठाने की बात कही है। कुल मिलाकर, यह मुलाकात अमेरिका–चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक और राजनीतिक तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं, ट्रंप और शी जिनपिंग की आसियान बैठक में हुए व्यापार समझौते के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:–

पहला, व्यापार युद्ध विराम विस्तार : दोनों देशों ने व्यापार युद्ध विराम समझौते को विस्तारित करने पर सहमति बनाई, जिससे व्यापारिक तनाव कम होगा।

दूसरा, टैरिफ वार टालना : अमेरिका ने 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी की थी, जिसे समझौते के तहत टाला गया। चीन ने अमेरिकी टैरिफ और निर्यात प्रतिबंधों पर सौहार्दपूर्ण वार्ता की सहमति दी।

तीसरा, फेंटेनाइल नियंत्रण : व्यापार के अलावा, फेंटेनाइल तस्करी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसे अमेरिकी पक्ष ने गंभीरता से उठाया। चतुर्थ, निर्यात नियंत्रण : चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स और अन्य प्रमुख विनिर्माण इनपुट पर निर्यात नियंत्रण पर बातचीत हुई, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थिर रह सके। पंचम, कृषि एवं तेल आयात : अमेरिकी किसानों से फसल खरीद और रूस से तेल खरीद को लेकर भी बहस हुई, जो दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद करेगी। षष्टम, वैश्विक आर्थिक स्थिरता : दोनों नेताओं ने वैश्विक बाजारों में स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। समझा जाता है कि इस समझौते से अमेरिका–चीन के व्यापारिक विवादों में कमी आने और वैश्विक आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने की उम्मीद है। इसप्रकार से यह बैठक रणनीतिक आर्थिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ट्रंप और शी जिनपिंग ने टैरिफ और निर्यात नियंत्रण पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि अमेरिका ने चीन पर 100 प्रतिष्ठित टैरिफ लगाने की योजना को अब टाल दिया है, जिससे बड़े टैरिफ युद्ध की आशंका कम हो गई है। दोनों देशों ने चीन की दुर्लभ पृथ्वी (त्तम म्तजी) मृदा पदार्थों के निर्यात नियंत्रण को कुछ समय के लिए स्थगित करने पर सहमति जताई है। इस समझौते को लेकर दोनों पक्षों की बातचीत को ष्रचनात्मक और गहनष् बताया गया है। वहीं, चीन ने भी यह खुलकर माना है कि निर्यात नियंत्रण को लेकर प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन में स्थिरता बनी रहे। इस कदम से व्यापार में संतुलन आएगा और दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा। इसके साथ ही, व्यापार युद्ध को खत्म कर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। बता दें कि इस सबके पीछे प्रमुख कारण अमेरिका द्वारा 1 नवंबर से नए 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की धमकी थी, जिसे चर्चा के बाद टाला गया। दोनों नेताओं की मुलाकात में इन मुद्दों को लेकर गंभीर और सकारात्मक बातचीत हुई है, जिससे व्यापारिक संबंध बेहतर हो सकेंगे। इसलिए, टैरिफ टालने और निर्यात नियंत्रण पर सहमति ने आगामी व्यापारीय विवादों को कम करने का मार्ग प्रशस्त किया है और एक संतुलित, स्थिर व्यापारिक वातावरण बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इन बातों से स्पष्ट है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के वैश्विक मायने बड़े और कई पक्षों से देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह बैठक अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे व्यापारिक तनाव, विशेषकर टैरिफ विवाद पर समाधान की उम्मीद जगाती है। बताया जाता है कि आगामी 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में दोनों देश के नेता मिलेंगे और अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 155 प्रतिशत से अधिक टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जिससे वैश्विक व्यापार में स्थिरता आ सकती है। इसके अलावा, इस मुलाकात में ताइवान की स्थिति, यूक्रेन युद्ध, और फेंटेनाइल की तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ट्रंप ने कहा है कि उनका उद्देश्य किसानों के हितों का संरक्षण करते हुए दोनों देशों के बीच व्यावहारिक और पूर्ण समझौता करना है। कहना न होगा कि यदि यह वार्ता सफल होती है, तो इससे न केवल अमेरिका और चीन के द्विपक्षीय संबंध सुधरेंगे, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी स्थिरता आएगी और ब्रिक्स देशों जैसे विकासशील देशों की स्थिति पर असर पड़ेगा। कुलमिलाकर यह मुलाकात एशिया–प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो, ट्रंप–जिनपिंग की मुलाकात विश्व के दो प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच आर्थिक, कूटनीतिक और क्षेत्रीय स्थिरता हेतु निर्णायक क्षण है, जिसका प्रभाव वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर गहरा होगा। ट्रंप–जिनपिंग की मुलाकात के संदर्भ में ताइवान नीति पर संभावित बदलावों के संकेत कुछ मुख्य बिंदुओं से समझे जा सकते हैं:–

पहला, अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को लेकर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भाषा में बदलाव किए, जिससे चीन नाराज हुआ। अमेरिका का कहना है कि वह ताइवान में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है और किसी भी एकतरफा बदलाव का विरोध करता है, लेकिन चीन इसे अमेरिका की गलत नीति मानता है। यह संकेत देता है कि अमेरिका ताइवान के साथ अपने अनौपचारिक संबंधों को जारी रखेगा पर चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी रहेगी।

दूसरा, ट्रंप प्रशासन ने अपने सहयोगी देशों से पूछा है कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनका क्या रुख होगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका संभावित सैन्य संघर्ष की स्थिति के लिए बहुपक्षीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, जो ताइवान के मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना सकता है।

इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2025 वापस लेने की मांग

मुंबई में 3 नवंबर की बैठक में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का फैसला

संवाददाता

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से मांग की है कि किसान, उपभोक्ता और कर्मचारी विरोधी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) 2025 तत्काल वापस लिया जाए। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 09 अक्टूबर को इस बिल का प्रारूप जारी किया है और स्टेक होल्डर्स से एक महीने के अंदर–अंदर टिप्पणी मांगी गई है। संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि मुंबई में 03 नवंबर को बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की बैठक हो रही है। इस बैठक में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी और बिजली कर्मचारी, किसानों और आम उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने बताया कि मुम्बई की बैठक में उप्र में चल रही

निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में भी राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया जाएगा। संघर्ष समिति ने आज जारी बयान में कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के माध्यम से केंद्र सरकार देश के संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। निजीकरण के बाद बिजली की दरें इतनी ज्यादा हो जाएगी जो किसानों और आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट बिल के सेक्शन 14,42 और 43 के माध्यम से निजी कंपनियों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों का नेटवर्क इस्तेमाल कर बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे और इसके एवज में वे सरकारी बिजली कंपनियों को व्हीलिंग चार्जेज देंगी जो नाम मात्र का होगा। उन्होंने कहा कि यह सरकारी क्षेत्र में विद्युत वितरण के अंत की शुरुआत होगी।संघर्ष समिति ने बताया कि नेटवर्क के मेंटेनेंस और उसके सुदृढ़ीकरण की सारी जिम्मेदारी सरकारी वितरण कंपनियों की होगी। इसका वित्तीय भार सरकारी विद्युत वितरण निगमों पर आयेगा। निजी कंपनियों को इस नेटवर्क के जरिए पैसा कमाने की छूट दी जा रही है।उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट बिल में निजी कंपनियों को यूनिवर्सल पावर सप्लाई का दायित्व नहीं होगा जिसका दुष्परिणाम यह होगा की निजी कंपनियां सरकारी कंपनी का नेटवर्क प्रयोग करके मुनाफे वाले औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली देंगी और घाटे वाले किसान और गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली देने का दायित्व सरकारी विद्युत वितरण निगम का होगा। परिणाम स्वरूप सरकारी विद्युत वितरण कंपनियां कंगाल हो जाएगी और उनके पास बिजली खरीदने और अपने कर्मचारियों को वेतन देने का भी पैसा नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि अमेंडमेंट बिल में सेक्शन 61 (जी) में संशोधन कर अगले 05 वर्ष में क्रॉस सब्सिडी समाप्त करने की बात लिखी है। इसके साथ ही बिल में यह प्रावधान किया गया है कि बिजली का टैरिफ कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होना चाहिए जिसका तात्पर्य है कि लागत से कम मूल्य पर किसी उपभोक्ता को बिजली न दी जाए। इसका मतलब यह हुआ कि किसानो को 05 हॉर्स पावर के पंप के लिए कम से कम 12000 रु प्रति माह बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें कम से कम 08 रु से 10 रु प्रति यूनिट हो जाएगी।

मिशन सशक्तिकरण समिति ने मनाया अपना पांचवा वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह

संवाददाता

लखनऊ। मिशन सशक्तिकरण समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा यूपी प्रेस क्लब में अपना पांचवा वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस

अवसर पर संस्था के पदाधिकार्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भरतनाट्यम नृत्यांगना यशिका शुक्ला ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। संस्था की संरक्षक डॉ. ज्योत्सना सिंह के द्वारा स्वागत उद्बोधन के माध्यम से संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों का परिचय देते हुए सभी का आभार एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित विभूतियां समाज सेविका रीता नाथ ,नेत्र चिकित्सक डॉ स्वाति पाल, पैडमैन ऑफ लखनऊ एवं सृजन फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अमित सक्सेना, नित्य धाम डांस अकैडमी की ओनर निशि मिश्रा , मिसेज उत्तर प्रदेश सम्मान से सम्मानित प्रतिमा सोनकर ,आर्मी आफिसर कर्नल नृपेंद्र सिंह की धर्मपत्नी निशी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर अभिनव, एवं नारायणी होंडा की ओनर शताक्षी गुप्ता को सम्मानित किया गया। बाल कलाकारों के द्वारा लोकगीत व नृत्य की सुंदर प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉ. शोभा दिक्षित भावना चंद्रदेव दीक्षित, मेहंदी हसन नकवी, साधना मिश्रा लखनवी, विमलेश गंगवार,तारा गुप्ता एवम एस के .त्रिवेदी जी के द्वारा काव्य पाठ किया गया पूरे कार्यक्रम का संचालन रेनू मिश्रा ने किया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष शारदा सिंह, प्रमुख संरक्षक सविता व्यास संरक्षक डॉ. शोभा दिक्षित भावना ,शशि तिवारी, नीरज नीरू, रश्मि लहर,प्रियंका सिंह,कविता सिंह, के द्वारा सभी को पौधा भेंट कर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के संरक्षक जी. एल.गांधी जी के द्वारा अंत में आभार व्यक्त करते हुए सभी को पुनः वार्षिकोत्सव की हार्दिक बधाई दी गई।

यूपी को जल्द मिल सकता है 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के रूप में नया प्रशासनिक केंद्र बनने की तैयारी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 76वां जिला बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। यह प्रस्तावित जिला प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के नाम

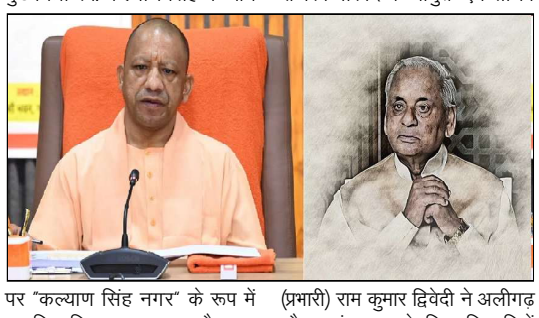

पर "कल्याण सिंह नगर" के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यह जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया जाएगा। नए जिले में अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी तहसील तथा बुलंदशहर की डिबाई तहसील शामिल होंगी। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और दिल्ली–एनसीआर से निकटता के कारण विकास की बड़ी संभावनाएं रखता है।पूर्व सांसद राजवीर सिंह 'राजू भैया', जो कल्याण सिंह के पुत्र हैं, ने 1 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने पिता की जन्मभूमि मढ़ौली गांव (अतरौली, अलीगढ़) को केंद्र बनाकर नया जिला बनाने की मांग की थी। उन्होंने इसे उनके योगदान के सम्मान और स्थानीय विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक बताया। मांग के बाद राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव (प्रभारी) राम कुमार द्विवेदी ने अलीगढ़ और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर नई जिला संरचना के औचित्य पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दोनों जिलों के प्रशासन को जनसंख्या, क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति और विकास क्षमता के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर राजस्व परिषद को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यदि रिपोर्ट सकारात्मक रही, तो यह प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद 2026 तक अमल में लाया जा सकता है। दिसंबर 2024 में 'जिला निर्माण संघर्ष समिति' ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अनूपशहर, डिबाई और शिकारपुर तहसीलों को मिलाकर कल्याण सिंह के नाम पर जिला बनाने की मांग की थी। यह प्रस्ताव न केवल प्रशासनिक सुविधा बल्कि कल्याण सिंह की विरासत के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के मढ़ौली गांव में जन्मे कल्याण सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता और दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे 1967 से लगातार अतरौली विधानसभा सीट से 10 बार विधायक बने। उन्होंने 2004 में बुलंदशहर से सांसद के रूप में भी कार्य किया। मुख्यमंत्री रहते 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। बाद में वे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। 2021 में निधन के बाद उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (एक्स) पर प्रस्ताव को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। कई लोग इसे हैशटैग के साथ साझा कर रहे हैं। समर्थक इसे भाजपा सरकार की "विकास और सम्मान" नीति का हिस्सा बता रहे हैं। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो "कल्याण सिंह नगर" उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा। इसके गठन से क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाएं, रोजगार और विकास के नए अवसर खुलेंगे।

संक्षिप्त

राजधानी में घाटों पर तेज बारिश के बीच सूर्य को अर्घ्य, तेज हवा में भी नहीं बुझे दिये

संवाददाता

लखनऊ। छठ महापर्व पर राजधानी लखनऊ में तेज बारिश के बीच भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। बारिश के चलते कुछ श्रद्धालुओं ने शुभकामना लिखे बैनर ही ओढ़ लिए। वहीं, जब अधिकतर ने छाते निकाले तो घाट पर छाते ही छाते नजर आए। वैसे तो लखनऊ में 51 घाटों पर छठ पूजन किया गया, लेकिन हर बार की तरह लक्ष्मण मेला घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ रही। महिला श्रद्धालुओं गोमती में खड़े होकर जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। एक महिला ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी को भखरा सिंदूर लगाया। आज अर्घ्य के साथ ही 36 घंटे से चल रहा निर्जला उपवास पूरा हो गया। व्रतियों ने घर जाकर पारण किया। व्रती महिलाएं बोलीं– छठी मईयां की आशीर्वाद से तेज हवा के बीच भी जलते दीये नहीं बुझे। ये बारिश छठी मइया के खुश होने के शुभ संकेत हैं।

खड़े ट्रक में कंटेनर ने मारी टक्कर, दो लोग गंभीर रूप से घायल

संवाददाता

लखनऊ। सोमवार देर रात रहीमाबाद थाना क्षेत्र के भतोइया स्थित गुलाल खेड़ा मोड़ के पास एक सड़क हादसा हो गया। हरदोई की ओर जा रहे कबाड़ लदे एक ट्रक को सड़क किनारे खड़े होने के दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कबाड़ लदे ट्रक के चालक गुलाम नबी (निवासी निर्धना थाना चेरथावाल, मुजफ्फरनगर) और कंटेनर पर सवार राशिद घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए मलिहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

आईटीओटी अलीगंज के प्रशिक्षार्थियों ने हासिल किया राष्ट्रीय गौरव

प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित प्रशिक्षुओं का हुआ अभिनंदन समारोह, सीआईटीएस परीक्षा में अव्वल 16 प्रशिक्षार्थी सम्मानित

संवाददाता

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र आईटीओटी अलीगंज ने प्रदेश का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है।इस संस्थान के 10 व्यवसायों में से 9 व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनमें कु. साक्षी चौरसिया ट्रेड सीएसए एवं कु. प्रीति कांडू ट्रेड इलेक्ट्रीशियन को गत 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि प्रदेश एवं संस्थान के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने आईटीओटी अलीगंज में सत्र 2024–25 के अखिल भारतीय सीआईटीएस परीक्षा–अगस्त 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त 16 मेधावी प्रशिक्षुओं तथा संस्थान स्तर पर चयनित 15 प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। इस अवसर पर निदेशक डी.के. सिंह को उनके नेतृत्व, कठोर परिश्रम और संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया।मुख्य अतिथि कपिल देव अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन 'स्किल्ड इंडिया' और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता 'कौशल युक्त उत्तर प्रदेश' को साकार करने में आईटीओटी लखनऊ जैसे संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारत के 151 सीआईटीएस संस्थानों में से उत्तर प्रदेश का आईटीओटी लखनऊ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर देश में कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित हमारे प्रशिक्षार्थी पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा हैं। यह गौरवपूर्ण क्षण है कि उत्तर प्रदेश के युवा प्रशिक्षक अब पूरे भारत में प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा उठा रहे हैं।

पत्नी ने कराई थी पति की हत्या, प्रेमी को तमंचा और कारतूस दिए

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ पुलिस लाइन के संविदा कर्मी की हत्या का मंगलवार को खुलासा हो गया। उसकी पत्नी ने प्रेमी से हत्या करवाई थी। हत्या के लिए उसने प्रेमी को तमंचा और कारतूस भी दिया था। प्रेमी ने संविदाकर्मी को अधिक शराब पिलाने के बाद सिर और पीठ में गोली मारी थी। शव को सड़क के किनारे फेंककर फरार हो गया था। शव बरामद होने के बाद छानबीन करने पहुंची पुलिस को मृतक की पत्नी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी थी। इससे उस पर शक गहराया था। साक्ष्य एकत्र करके पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने आज मंगलवार को आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। घटना 25 अक्टूबर की रात बीकेटी थाना क्षेत्र में आउटर रिंग रोड पर मामपुर बाना गांव के पास की है। मामपुर बाना निवासी 25 वर्षीय प्रमोद गौतम का खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस ने उसकी पत्नी चांदनी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच में चांदनी और उसका प्रेमी बच्चा लाल निवासी बबरू, बांदा का नाम सामने आया, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार

किया। एडीसीपी अमोल मुकुट के अनुसार, चांदनी के पास फरवरी 2025 में बच्चा लाल की रॉन्ग कॉल आई। दोनों ने बात की। उसके बाद से दोनों बातचीत करने लगे। इसके बाद दोनों सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ गए। कुछ ही दोनों में दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। इसका कारण यह भी रहा कि इसके पहले चांदनी किसी अन्य पुरुष से बातचीत करती थी, लेकिन उस दौरान उससे बातचीत बंद थी। इस वजह से वह बच्चा लाल से देर तक बातें करने लगी। जुलाई में चांदनी की नंद की शादी थी। उस दौरान बच्चा लाल उनके घर आया। चांदनी ने उसे अपनी सहेली का देवर बताकर सप्ताहभर घर में रखा। इस दौरान दोनों की नजदीकियां और बढ़ गईं। दोनों में शारीरिक संबंध भी बने। उसने शादी के कामों में परिवार के लोगों का हाथ भी बंटाया। शादी की भाग–दौड़ की वजह से किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि ननद की शादी के बाद चांदनी बच्चा लाल के साथ दिल्ली चली गई। उसने घरवालों को बताया कि सहेली के साथ काम करने जा रही है। दोनों करीब 20 दिन तक दिल्ली में साथ रहे। इस दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद चांदनी लखनऊ लौट आई थी। उसके बाद भी दोनों लखनऊ में छिप–छिपकर मिलते रहे। पुलिस की जांच में आया कि मृतक प्रमोद गौतम शराब का आदी था। शराब के नशे में वह चांदनी से मारपीट करता था। इस वजह से चांदनी ने प्रमोद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने बच्चा लाल से प्रमोद की हत्या करने को कहा। उसने मना किया। इस पर चांदनी ने कहा कि वह नहीं मारेगा, तो किसी दूसरे से मरवा देगी। इससे गुस्से में आकर बच्चा लाल प्रमोद की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। पुलिस की पूछताछ में बच्चा लाल ने बताया कि 25 अक्टूबर की शाम वह प्रमोद से मिला। उसे शराब पिलाने के बहाने गांव के पास आउटर रिंग रोड के किनारे ले गया। वहां दोनों ने शराब पी। उसने कम शराब पी और प्रमोद को अधिक पिलाई। प्रमोद जब नशे में हो गया, तो तमंचे से उसके पीठ में गोली मार दी। वह जमीन पर गिर गया, तो एक गोली उसके सिर में मारी। उसके बाद फरार हो गया। पकड़े जाने के बाद दोनों एक–दूसरे पर प्रमोद की हत्या का दोष मढ़ने लगे। बच्चा लाल ने कहा कि चांदनी ने तमंचा और कारतूस की व्यवस्था की। वहीं, चांदनी ने कहा कि बच्चा लाल खुद तमंचा लेकर आया था। पुलिस पूछताछ के आधार पर तमंचा के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रमोद और चांदनी की करीब 8 साल पहले शादी हुई थी। दोनों की 2 बेटियां हैं। पिता की हत्या और मां के जेल जाने के कारण दोनों अकेली रह गई हैं। परिवार के अन्य सदस्य उनकी देखरेख कर रहे हैं।

काकोरी पेशाब कांड पीड़ित से मिले कांग्रेस कार्यकर्ता, मेडिकल बोर्ड करे जांच

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काकोरी पेशाब कांड पीड़ित रामपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों ने कहा आरोपी हार्ट अटैक का बहाना बना रहा है। उसे निजी से सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। मेडिकल बोर्ड से उसका हेल्थ चेकअप कराया जाए।उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर कांग्रेस के विधि विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को काकोरी पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने दलित उत्पीड़न के शिकार रामपाल से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव कानूनी सहायता का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश कोऑर्डिनेटर एडवोकेट आसिफ रिजवी ने किया। उन्होंने कहा संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और कांग्रेस पार्टी हमेशा वंचितों के साथ खड़ी है। रिजवी ने राहुल गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर न्याय और समानता की लड़ाई लड़ने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल में शामिल राजेश विद्यार्थी ने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने को हर नागरिक का कर्तव्य बताया। सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष अक्षय कटिहार ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार लोकतंत्र के लिए चिंताजनक हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले काकोरी क्षेत्र में दलित समाज के रामपाल के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना हुई थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी को अभी तक निजी अस्पताल में भर्ती रखा गया है, जबकि उसे सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। इस संबंध में एडवोकेट आसिफ रिजवी ने इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौर से बातचीत की। इंस्पेक्टर ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी को दिल का दौरा पड़ने के कारण उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इसे संदेहास्पद बताते हुए आरोपी को सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग की, ताकि बीमारी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से एक मेडिकल बोर्ड गठित करने और आरोपी को तुरंत सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग दोहराई है।

भाई-बहन को 16 सेकेंड में 20 थप्पड़ जड़े, फूट-फूटकर रोई युवती बोली-एफआईआर नहीं करते हैं

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में 8–10 लोगों ने फ्लैट में घुसकर भाई–बहन को जमकर पीटा। 16 सेकेंड में बहन–भाई को 20 थप्पड़ मारे। गाली–गलौज करते हुए मॉस्किटो रॉकेट से भी पीटा। पीड़ित भाई–बहन ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डर की वजह से पीड़ित भाई–बहन 4 दिन से फ्लैट छोड़कर दोस्त के यहां रुके हैं। पीड़ित युवती ने मड़ियांव थाने के बाहर खड़ी होकर वीडियो बनाया है। रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी है। कानून–व्यवस्था को लेकर पुलिस और सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। वीडियो मंगलवार को सामने आया है। घटना 23 अक्टूबर को मड़ियांव थाना क्षेत्र के एल्डिको सिटी के कुटीर अपार्टमेंट में हुई। अपार्टमेंट में शालू चौरसिया भाई के साथ किराए पर रहती हैं। उनका आरोप है कि पार्किंग विवाद के बाद सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट और अन्य निवासियों ने मारपीट की है।मंगलवार को सामने आए 50 सेकेंड के वीडियो में एक युवती मड़ियांव थाने के बाहर खड़ी होकर रोते दिख रही है। रोते हुए युवती खुद का नाम शालू चौरसिया बताती है। वीडियो में कह रही है कि श्वहां का अध्यक्ष मेरे साथ मारपीट कर रहा था। छेड़खानी कर रहा था और मेरा फोन जबरदस्ती छीन करके ले गया था। युवती कहती है कि मैं 4 दिन से मड़ियांव थाने का चक्कर लगा रही हूं। ये लोग एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं। क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं इसका कारण भी नहीं बता रहे हैं। मैं 4 दिन से अपने रूम पर भी नहीं जा रही हूं। अपने दोस्त के यहां भाई के साथ रह रुकी हुई हूं। यही है यूपी पुलिस की सच्चाई। यही लोग कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। एफआईआर ही नहीं दर्ज करते हैं और कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। बेटी बचाओ और न जाने क्या–क्या नारा ये लोग बेटियों का देते हैं। यह वीडियो सोमवार को बनाया गया है। इस मामले का 1.04 सेकेंड का एक और वीडियो सामने आया है। उसमें युवती और उसका भाई फ्लैट में आते हैं। भाई गेट की कुंडी बंद करता है। उसके बाद युवती कहती है कि ऑनर को फोन लगावो। करीब 30 सेकेंड बाद बाहर से गेट खटखटाने की आवाज आती है। युवती भाई से कहती है कि रुको गेट मत खोलो। उसके बाद युवती गेट खोलती है। गेट खुलते ही सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक व्यक्ति लगभग दौड़ते हुए फ्लैट में घुसता है और युवती को जोरदार थप्पड़ जड़ने लगता है। भाई उसे बचाने की कोशिश करता है। इस बीच अन्य युवक भी अंदर घुस आते हैं। युवती और उसके भाई को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारते हैं। उनमें से एक युवक बेड पर रखा मॉस्किटो रॉकेट उठाकर उससे उनकी पिटाई करने लगता है। इस दौरान हमलावर गाली–गलौज करते हैं। यह वीडियो फ्लैट में रखे मोबाइल में रिकार्ड हो जाता है। पुलिस के मुताबिक, शालू चौरसिया भाई के साथ अपार्टमेंट में किराए पर रहती हैं। वह दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। शालू ने अपार्टमेंट में अपनी स्कूटी खड़ी की थी। आरोप है कि गार्ड ने उसे किनारे कर दी, तो वह भड़क गई। गार्ड से गाली–गलौज करने लगी। गार्ड ने जब इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो उसका मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद गार्ड ने सोसाइटी के पदाधिकारियों को बुलाया। तब तक शालू अपने फ्लैट में चली गई। उसके बाद सोसाइटी प्रेसिडेंट और अन्य निवासियों ने उनके फ्लैट में घुसकर मारपीट की। सोसाइटी के प्रेसिडेंट रमन सिंह ने बताया कि 6 सितंबर को युवती ने जहां पर स्कूटी खड़ी की थी, वहां नहीं थी। अलग खड़ी थी। उसने गार्ड से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। गार्ड ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत चल रही है। इस पर युवती ने डंडा मारकर सीसीटीवी तोड़ दिया। उसके दूसरे दिन उनके खिलाफ मड़ियांव थाने में छेड़खानी की शिकायत दी। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया, तो युवती उन्हें पहचान नहीं पाई। इस पर मामला खत्म हो गया। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि 23 सितंबर को स्कूटी खड़ी करने को लेकर फिर से युवती का विवाद हो गया।

दुबग्गा पावर हाउस पर लोगों का प्रदर्शन, संविदा कर्मचारी को न्याय दिलाने की मांग

संवाददाता

लखनऊ। दुबग्गा उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मचारी धीरज गौतम के दुर्घटना प्रकरण में कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यह धरना भारतीय किसान यूनियन (श्रमिक जनशक्ति) के बैनर तले दुबग्गा मछली मंडी गेट के पास आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने बताया घटना 27 सितंबर की रात हुई थी। धीरज गौतम ड्यूटी के दौरान विद्युत लाइन जोड़ने का कार्य कर रहे थे। आरोप है कि विभागीय लापरवाही के चलते बिना किसी पूर्व सूचना के लाइन चालू कर दी गई, जिससे धीरज को करंट लग गया। करंट लगने से धीरज गंभीर रूप से झुलस गए थे। इलाज के दौरान उनके दोनों हाथ काटने पड़े। परिजनों ने 18 अक्टूबर को प्रबंध निदेशक मध्यांचल को पत्र लिखकर सहायता की मांग की थी। निदेशक (तकनीकी) हरीश बंसल ने इलाज का पूरा खर्च और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को कोई सहायता नहीं मिली है। इसी के विरोध में न्याय की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया है। धरना स्थल पर थाना दुबग्गा के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बातचीत की।

एनटीपीसी सिंगरौली चिल्काझील में हजारों श्रध्दालुओं ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया

बीएनई

एनटीपीसी सिंगरौली। शक्तिनगर में छठ पूजा का आयोजन इस वर्ष भी विधिपूर्वक और भव्यता से संपन्न हुआ। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एनटीपीसी परियोजना ने छठ पूजा के आयोजन के लिए व्यापक प्रबंध किए, ताकि यह पर्व श्रद्धा और सुरक्षा के साथ मनाया जा सके। इस आयोजन में श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की गईं। चिल्काझील की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा गया और श्रद्धालुओं के लिए समुचित जलपान, साफ–सफाई, चेंजिंग रूम और प्रसाधन जैसे कई जरूरतमन्द व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया। साथ ही, श्रद्धालुओं के उत्साह को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त रोशनी, सजावटी लाईट और पेयजल की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त संख्या में सी.आई.एस.एफ सुरक्षा कर्मी, पुलिस और निजी गार्डों की तैनाती की गई। आयोजन स्थल पर पूरे क्षेत्र की निगरानी सी.सी.टी.वी व ड्रोन कैमरों से की गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से निरंतर आवश्यक सूचना प्रदान की गई। खोये हुए परिवार जनों को भी यहां के अधिकारियों द्वारा मिलाया गया। घाट के चारों ओर सुरक्षा तैराक तैनात किए गए थे और झील में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से नाव, रस्सी और हुक की व्यवस्था की गई थी। एनटीपीसी द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंध, घाट की सफाई, रास्तों की साफ–सफाई, सुरक्षा बैनर सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं ने आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आयोजन में हर व्यक्ति की सुरक्षा और संतुष्टि का विशेष ध्यान रखा गया। इस शुभ अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली के परियोजना प्रमुख श्री संदीप नायक ने भी सपत्नीक छठी मईया को अर्घ दिया। एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा छठ पूजा के आयोजन में सहयोग देने के लिए सभी श्रद्धालुओं, पुलिस प्रशासन, सी.आई.एस.एफ, निजी गार्ड, यूनियन और एसोसिएशन के सदस्य गण तथा आयोजन समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कुनकुरी छठ घाट में सूर्य को दिया अर्घ्य : प्रदेश के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की

बीएनई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने छठ महापर्व के पावन अवसर पर जशपुर जिले के कुनकुरी छठ घाट में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा सूर्य उपासना और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व जैसे आस्था और श्रद्धा से जुड़े पर्व में शामिल होने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि कुनकुरी छठ घाट के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 5 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

साल के अंत तक बदल सकता है फेड का नेतृत्व

जेरोम पॉवेल की कुर्सी पर पांच दावेदार

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका में अगले साल फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की जगह कौन लेगा, इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने पांच संभावित उम्मीदवारों के नामों की पुष्टि की है। साल के अंत नए अध्यक्ष की उम्मीद एशिया यात्रा के दौरान एयर फोर्स वन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया से बातचीत में बेसेंट ने कहा कि वे आने वाले हफ्तों में दूसरे दौर की इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी करेंगे और थैंक्सगिविंग के ठीक बाद ट्रंप के सामने अच्छी सूची पेश करेंगे। ट्रंप साल के अंत तक नए अध्यक्ष पर फैसला करने की उम्मीद जता चुके हैं। यह नाम फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के दौड़ में शामिल हैं फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर और मिशेल बोमन पूर्व फेड के गवर्नर केविन वार्श व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ब्लैकरॉक के वरिष्ठ मैनेजिंग डायरेक्टर रिक रीडर बड़ी नीतिगत दिशा बदलने के संकेत बेसेंट खुद फेड की नीतियों और 2008–09 की वित्तीय मंदी से लेकर महामारी के दौर तक उठाए गए कदमों के प्रखर आलोचक रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नया नेतृत्व आने पर फेड की मौद्रिक नीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप करते आ रहे हैं पॉवेल के फैसलों की आलोचना इस बीच, ट्रंप ने सोमवार को पॉवेल पर किए गए अपने पुराने हमलों को दोहराया और आरोप लगाया कि ब्याज दरों में कटौती करने में उन्होंने देरी की। पॉवेल का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे पास इस समय एक ऐसा व्यक्ति है, जो बिल्कुल भी समझदार नहीं है। उन्हें बहुत पहले ही ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए थी। उम्मीद है कि फेड बुधवार को इस साल दूसरी बार अपनी मुख्य ब्याज दरों में कटौती करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति इस साल के अंत तक फेडरल रिजर्व के नए चेयर का नाम तय करना चाहते हैं। यह जल्दबाजी फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल की स्थिति से जुड़ी उन पेचीदगियों को भी दर्शाती है, जो व्हाइट हाउस के लिए चुनौती हो सकती हैं। पॉवेल का कार्यकाल अगले साल मई में समाप्त हो रहा पॉवेल का चेयरमैन कार्यकाल अगले साल मई में खत्म हो रहा है। हालांकि, वे जनवरी 2028 तक फेड के सात गवर्नरों में से एक के रूप में बोर्ड में बने रह सकते हैं। ऐसा होना दुर्लभ है, लेकिन इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं। अगर पॉवेल बोर्ड में रहते हैं, तो ट्रंप को कई वर्षों तक नए गवर्नर की नियुक्ति का मौका नहीं मिलेगा यानी नीति नियंत्रण के लिए कम गुंजाइश। ट्रंप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को नामित कर सकते हैं फिर भी ट्रंप के पास एक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। फेड के मौजूदा गवर्नर स्टीफन मिरान, जिन्हें ट्रंप ने 16 सितंबर को नियुक्त किया था, उनकी अवधि 31 जनवरी 2026 तक है। ट्रंप पॉवेल को रिप्लेस करने के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को इसी सीट पर नामित कर सकते हैं और मई में पॉवेल के पद छोड़ने पर उसी व्यक्ति को फेड चेयर बनाया जा सकता है।

संक्षिप्त

अदाणी समूह दिघी पोर्ट में 42500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगा, एमओयू पर हस्ताक्षर

एजेंसी

नई दिल्ली। अदाणी समूह ने महाराष्ट्र के तटीय कोंकण क्षेत्र में दिघी बंदरगाह परियोजना में 42,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने पर हामी भरी है। सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि समूह की प्रमुख इकाई अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) की ओर से संचालित दिघी पोर्ट्स ने बंदरगाह के विस्तार और संबंधित गतिविधियों के लिए 42,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में कहा कि यह निवेश भारत समुद्री सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर सरकार की ओर से हस्ताक्षरित 56,000 करोड़ रुपये से अधिक के 15 समझौतों का हिस्सा है। अदाणी समूह की नई प्रतिबद्धता का पूरा विवरण पूरा जारी नहीं किया गया है। दूसरे सबसे अमीर भारतीय गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले समूह ने 2021 में 705 करोड़ रुपये की विजयी बोली लगाकर दिवालिया घोषित हो चुकी दिघी पोर्ट परियोजना का अधिग्रहण किया था। समूह ने इसके विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इससे पहले भारत समुद्री सप्ताह के दौरान महाराष्ट्र में बंदरगाहों के विकास से संबंधित तीन सत्र आयोजित किए गए। इन तीन सत्रों में से एक सत्र महाराष्ट्र सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच 15 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर का था। ये समझौता ज्ञापन जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, बंदरगाह अवसंरचना और जल परिवहन के विकास से संबंधित थे। सबसे बड़ा समझौता ज्ञापन अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एसईजेड) के साथ हस्ताक्षरित किया गया, जिसका मूल्य 42,500 करोड़ रुपये है।

भारत से फिर जुड़ेंगे दिग्गज मुक्केबाजी कोच सेंटियागो, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने साई को भेजा प्रस्ताव

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय मुक्केबाजी टीम के पूर्व विदेशी प्रशिक्षक और हाई परफॉरमेंस डायरेक्टर अर्जेंटीनी मूल के दिग्गज स्वीडिश कोच सेंटियागो निएवा एक बार फिर भारतीय मुक्केबाजों से जुड़ने जा रहे हैं। सेंटियागो इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई मुक्केबाजी टीम के मुख्य प्रशिक्षक हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) उन्हें पुरुष टीम के मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर जोड़ रहा है। बीएफआई ने सेंटियागो के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को प्रस्ताव भेजा है। अनुबंध सिरे चढ़ा तो वह अब तक के सबसे महंगे विदेशी मुक्केबाजी कोच होंगे। उन्हें 12 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग साढ़े 10 लाख रुपये) प्रति माह के वेतन पर लाया जा रहा है। सेंटियागो टोक्यो ओलंपिक के बाद तक भारतीय मुक्केबाजी टीम के हाई परफॉरमेंस डायरेक्टर थे। पांच वर्ष तक भारत से जुड़े रह चुके हैं सेंटियागो 2017 में भारतीय मुक्केबाजी टीम के साथ जुड़े थे और 2022 तक उन्होंने भारतीय मुक्केबाजों को तराशा। उनकी कोचिंग में भारत के सर्वाधिक नौ मुक्केबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए थे, इनमें पांच पुरुष मुक्केबाज शामिल थे। हालांकि टोक्यो में देश के किसी भी मुक्केबाज का पदक नहीं जीतना उनके भारत छोड़ने का कारण बना। उनकी कोचिंग में भारत ने 2019 की विश्व चौंपियनशिप में दो पदक जीते और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। विश्व चौंपियनशिप में दिया वापसी का प्रस्ताव सूत्र बताते हैं कि हाल ही में हुई लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चौंपियनशिप के दौरान ही बीएफआई ने सेंटियागो को वापस भारतीय टीम के साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया। उनके अनुबंध पर अभी साई और खेल मंत्रालय की अंतिम मुहर लगना बाकी है। सेंटियागो की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाजों ने भी अच्छी प्रगति की है। पेरिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड 12 मुक्केबाज खेले। इनमें दो ने पदक भी जीते। सेंटियागो भारत से पहले स्वीडन के मुक्केबाजों को प्रशिक्षित कर चुके हैं।

शेयर बाजार ने बढ़त के साथ की शुरुआत, सेंसेक्स करीब 126 अंक तो निफ्टी 40 प्वाइंट चढ़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती और अमेरिका–चीन व्यापार समझौते की संभावनाओं से प्रेरित होकर मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 125.93 अंक चढ़कर 84,904.77 अंक पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 39.8 अंक बढ़कर 26,005.85 अंक पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे गिरकर 88.40 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों का हाल सेंसेक्स की कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, अडानी पोर्ट्स, टाइटन और मारुति प्रमुख लाभ में रहीं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स पिछड़ गए। विदेशी बाजारों में रहा मिला–जुला रुख एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक नीचे कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग ऊपर कारोबार कर रहे थे। सोमवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक दायरे में बंद हुए। इन पांच कारणों से बाजार में दिखी तेजी मेहता लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, ष्बाजार की धारणा सकारात्मक बनी हुई है, जिसे पांच उत्प्रेरकों का समर्थन प्राप्त हैरू अमेरिका में सीपीआई में नरमी से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं, अमेरिका–चीन व्यापार समझौते की संभावनाएं, हाल के सत्रों में एफआईआई का प्रवाह, वॉल स्ट्रीट सूचकांकों का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना और दूसरी तिमाही की आय की मजबूत शुरुआत। फेड ब्याज दरों में कर सकता है।

आरबीआई ने लौटाई जना एसएफबी की यूनिवर्सल बैंक अर्जी

शेयरों में आई करीब तीन प्रतिशत की गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने की कोशिश में झटका लगा है। बैंक ने मंगलवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसकी यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए दी गई आवेदन वापस कर दी है। यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिलने का मतलब किसी बैंक को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिलने का मतलब है कि वह अब एक ही छत के नीचे वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग सहित कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है। इसका मतलब है कि यह ग्राहकों को जमा, ऋण, निवेश बैंकिंग, संपत्ति प्रबंधन और अन्य वित्तीय समाधानों सहित सभी वित्तीय जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान कर सकता है। आरबीआई ने आवेदन वापस करने का कारण स्पष्ट नहीं किया लघु वित्त बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अजय कंवल के अनुसार, जून में दायर आवेदन को सोमवार देर शाम लौटाया गया है। हालांकि, आरबीआई ने आवेदन वापस करने के पीछे की सटीक वजहें साझा नहीं की हैं। यह वापसी है, अस्वीकृति नहीं– कंवल कंवल ने कहा कि हम जल्द ही समझेंगे कि जवाब के पीछे असल कारण क्या है और नियामक की उम्मीदों के मुताबिक सुधार करेंगे। हमें यह बात ध्यान रखना होगी कि यह वापसी है, अस्वीकृति नहीं। कंवल ने कहा कि वह इस सप्ताह के अंत में आरबीआई के शीर्ष अधिकारियों के साथ यूनिवर्सल बैंक आवेदन को वापस करने के सटीक कारणों पर चर्चा करेंगे, और बैंक द्वारा दोबारा आवेदन करने से पहले उन्हें ठीक कर लेंगे। हालांकि, उन्होंने नए आवेदन के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई। बैंक के संचलान पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा उन्होंने आगे कहा है कि बैंक के वर्तमान संचालन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक एसेट साइड पर देखा जाए तो जाना एसएफबी को वैसे भी लगभग वही सभी गतिविधियां करने की अनुमति है, जो यूनिवर्सल बैंक करते हैं। कंवल ने स्वीकार किया कि को–लेंडिंग की सुविधा नहीं होना एक सीमितता है, पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसे बैंक अपने बिजनेस मॉडल पर किसी बड़ी बाधा के रूप में नहीं देखता। फंडिंग कॉस्ट कम करने की योजना टली कंवल के अनुसार, अगर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मिल जाता, तो बैंक को लायबिलिटी साइड पर फायदा मिलता और फंड की लागत घटती। लेकिन अब इन योजनाओं को फिलहाल टालना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाल में बैंक की पैरेंट कंपनी स्ट्रक्चर में हुए बदलाव का यूनिवर्सल बैंक बनने की आकांक्षा से कोई संबंध नहीं था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिली थी हरी झंडी बता दें कि इस साल की शुरुआत में आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को परिभाषित समयावधि के भीतर यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए इन–प्रिंसिपल मंजूरी दी थी। जाना एसएफबी की अर्जी ने भी निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाई थीं, जिससे इसके शेयर में तेजी देखी गई थी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में आई गिरावट आरबीआई की ओर से अर्जी वापस किए जाने के बाद बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार सुबह करीब 09:57 बजे बीएसई पर जाना एसएफबी का शेयर 2.79% गिरकर 443.95 पर कारोबार कर रहा था।

एडवांस बुकिंग में प्रभास की फिल्म बाहुबली द एपिक का जलवा, रिलीज होने से पहले ही कमा लिए करोड़ों

एजेंसी

भारतीय सिनेमा का सबसे भव्य अध्याय 'बाहुबली' एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रहा है। एस एस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन अब रिलीज के लिए तैयार है। रिलीज से पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग में झंडे गाड़ दिए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की टिकटें बिकी रिपोर्ट्स के अनुसार, 'बाहुबलीरू द एपिक' के री–एडिटेड वर्जन की बुकिंग खुलते ही मात्र कुछ घंटों में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की टिकटें बिक गईं।

हैदराबाद समेत कई शहरों में शो मिनटों में 'हाउसफुल' हो गए। फिल्म का यह नया रूप 'वन एपिक कट' के नाम से पेश किया गया है, जिसमें 'बाहुबलीरू द बिगिनिंग' और 'बाहुबली 2 द कन्क्लूजन' को एक साथ जोड़कर एक शानदार सिनेमैटिक अनुभव बनाया गया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रति घंटे पांच हजार से अधिक टिकटें बिक रहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रच रहा है इतिहास केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी 'बाहुबलीरू द एपिक' ने रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है।

उत्तर अमेरिका में फिल्म ने +200,000 (करीब 1.6 करोड़) की एडवांस बुकिंग कर ली है, जो किसी भी भारतीय री–रिलीज फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दुनियाभर में फिल्म के प्री–सेल्स 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जो दर्शाता है कि राजामौली और प्रभास की जोड़ी का जादू अब भी बरकरार है। राजामौली और प्रभास की हिट जोड़ी इस फिल्म का एस.एस. राजामौली ने निर्देशन किया और वी विजयेंद्र प्रसाद ने इसकी कहानी लिखी। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन और सत्यराज जैसे कलाकारों ने इसमें शानदार काम किया। 31 अक्टूबर को री–रिलीज हो रही फिल्म फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। इसे चार भाषाओं में रिलीज किया जाएगा– हिंदी, मलयालम, तेलुगु और तमिल। फिल्म की एडवांस बुकिंग से साफ हो गया है कि एक बार फिर पर्दे पर बाहुबली का जादू चलने वाला है।

भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने जीता स्वर्ण पदक, उज्बेकिस्तान के जालोलोव को हराया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने अंडर–23 विश्व कुश्ती चौंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सुजीत ने खिताबी मुकाबले में उज्बेकिस्तान के उमिदजोन जालोलोव को एकतरफा अंदाज में 10–0 से हराया। दोनों पहलवानों के बीच यह मुकाबला चार मिनट 54 सेकेंड तक चला जिसके बाद रेफरी ने भारतीय पहलवान को विजेता घोषित किया। पदक का रंग बदलने में सफल रहे सुजीत सुजीत ने इस तरह उज्बेकिस्तान के पहलवान पर तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत दर्ज की। इससे पहले सुजीत ने कभी विश्व खिताब नहीं जीता था, लेकिन उन्होंने 2022 और 2025 में अंडर–23 एशिया खिताब और 2022 में अंडर–20 एशियन चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। सुजीत ने पिछले साल इसी चौंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, लेकिन इस बार वह पदक का रंग बदलने में सफल रहे। सुजीत का विश्व चौंपियनशिप में सफर सुजीत ने अपने पहले दो बाउट तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीते थे। उन्होंने मोलदोवा के फिओदोर किएवदारी को 12–2 से और पोलैंड के डोमिनिक जाकूब को 11–0 से परास्त किया था। क्वार्टर फाइनल में वह बशीर मागोमेदोव से पीछे चल रहे थे, लेकिन 4–2 से मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे थे। सेमीफाइनल में सुजीत ने जापान के युतो निशियुची को 3–2 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743